न्यायमूर्ति जे.वी. गुप्ता के समक्ष

दौलत राम चैरिटेबल ट्रस्ट व अन्य,

- याचिकाकर्ता,

बनाम

राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा व

अन्य, *- प्रतिवादी।*

1989 *की सिविल रिट याचिका संख्या* 9981

5 अक्टूबर, 1989.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 *का 52) - धारा 10(1) (के) - फार्मेसी अधिनियम,* 1948 - *एस.एस.* 10(1), 12(1) और 46- *शिक्षा विनियम,* 1982- रेगुलेशन 7 और 12- *फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत निजी फार्मेसी कॉलेज, प्रवेश के लिए चयन कर रहा है - फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबद्ध निजी कॉलेज - केंद्रीय परिषद का आदेश है कि निजी और सरकारी संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश केंद्रीय रूप से किया जाएगा - उल्लंघन निजी महाविद्यालय को संबद्धता समाप्ति के लिए उत्तरदायी बनाने का आदेश - निदेशक। तकनीकी शिक्षा, हरियाणा सूचित कर रहा है कि किए गए प्रवेशों को अमान्य घोषित कर दिया गया है - ऐसे आदेश की वैधता - निजी कॉलेज - क्या वह अपने स्वयं के प्रॉस्पेक्टस के अनुसार प्रवेश दे सकता है।*

अभिनिर्धारित किया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का 52) याचिकाकर्ता संस्थान पर लागू नहीं होता है। इसकी धारा 10 की उपधारा 1 खंड (के) के अंतर्गत परिषद के कर्तव्य बताए गए हैं। उनमें से एक संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नए तकनीकी संस्थान शुरू करने और कार्यक्रमों के नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी देना है। इस प्रकार, ऐसा अधिनियम नए तकनीकी संस्थानों पर लागू होता है, और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से कार्यक्रमों के नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए लागू होता है। इस प्रकार, ऐसा अधिनियम नए तकनीकी संस्थानों पर लागू होता है, न कि उन संस्थानों पर जिन्हें भारतीय फार्मेसी अधिनियम के तहत पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा, पहले अधिनियम को इस अधिनियम संख्या 52, 1987 द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। दोनों अलग-अलग कार्य कर रहे हैं और इसलिए, बोर्ड याचिकाकर्ता के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए 1987 के उक्त अधिनियम 52 से कोई सहायता नहीं ले सकता है - जब प्रवेश दिया गया हो। उत्तरदाताओं द्वारा इसे किसी भी प्रकार की कोई अनुदान सहायता नहीं दी जा रही है।

(पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार फार्मेसी अधिनियम के अध्याय II की धारा 12 के तहत विचार किए गए अध्ययन और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के संबंध में कोई नियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं थी।

(पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया कि संस्थान में दाखिले को प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रवेश प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाला कोई भी संस्थान असंबद्धता के लिए उत्तरदायी होगा

"ऐसा आवशायक नहीं-इसी प्रकार, यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी संस्थान द्वारा अपने स्तर पर इस कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रवेश दिया जाता है, तो ऐसे प्रवेश पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा और प्रवेशित छात्र का पंजीकरण नहीं किया जाएगा और उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा", याचिकाकर्ता संस्थान के संबंध में भी मान्य नहीं है।

(पैरा 19)

सिविल रिट याचिका अन्तर्गत 226/227 *के तहत निम्नानुसार प्रार्थना की गई है:*
-

(i) मैंडमस *की रिट जारी की जाए ताकि विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-2) को अवैध घोषित किया जा सके और उसे रद्द किया जा सके और उत्तरदाताओं को नीति अनुबंध पी-2 पर कार्य करने से रोका जा सके। आक्षेपित आदेश पर अमल करने से।*

(ii) यह *कि उत्तरदाताओं पर पूर्व सेवा और अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए;*

(iii) याचिकाकर्ताओं के मामले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाए ;

(iv) संपूर्ण लागत सहित रिट याचिका की अनुमति दी जाए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को कोई अन्य राहत भी दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से आर.एस. मोंगिया, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एल. गुप्ता के साथ।

प्रतिवादिगण की ओर से एस.सी. मोहंता, ए.जी. हरियाणा ।

जी सी गर्ग. वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता गुप्ता के साथ नौबत सिंह पंवार, इण्टरवीनर।

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.वी. गुप्ता,

(1) यह निर्णय 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11525, 11566, 12033, 11769, 11768 का भी निपटान करेगा क्योंकि इसमें शामिल प्रश्न इन सभी मामलों में समान हैं।

(2) इन रिट याचिकाओं में निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी2 दिनांक 13 जुलाई 1989 की

धमकी देते हुए कि कोई भी छात्र सीधे किसी भी संस्थान/पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना चाहता है, वह अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसा करेगा, और ऐसे छात्रों की परीक्षा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड हरियाणा, आदि द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी,**को चुनौती दी गई है।**

(3) याचिकाकर्ता एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसे "दौलत राम चैरिटेबल ट्रस्ट" के नाम से जाना जाता है, जो महर्षि कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तरावड़ी जिला करनाल चला रहा है। उक्त कॉलेज में सत्र 1984-85 से फार्मेसी में डिप्लोमा की कक्षाएं चल रही हैं। कॉलेज और कॉलेज द्वारा संचालित अध्ययन के पाठ्यक्रम को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है, जैसा कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 के रूप में जाने जाने वाले केंद्रीय अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। उक्त कॉलेज पूरी तरह से निजी और गैर-सहायता प्राप्त है और इसमें एक भी पैसा नहीं मिलता है। यह या तो सहायता के रूप में या कॉलेज द्वारा अपने शिक्षण कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन की प्रतिपूर्ति के रूप में या किसी अन्य तरीके से या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या उनके किसी उपकरण या एजेंसियों से।

(4) फार्मेसी में डिप्लोमा के छात्रों को निर्देश देना और उनका पंजीकरण आदि, उक्त फार्मेसी अधिनियम 1948 द्वारा शासित होते हैं, जिसकी धारा 10 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (इसके बाद सेंट्रल काउंसिल कहा जाता है), केंद्रीय की मंजूरी के साथ सरकार ने 8 जुलाई, 1982 की अधिसूचना के *माध्यम* से शिक्षा विनियम तैयार किए हैं। अधिनियम और अधिनियम के तहत बनाए गए शिक्षा विनियम फार्मेसी में डिप्लोमा और उसके बाद के पंजीकरण के लिए अकादमिक अध्ययन के लिए एक पूर्ण आचार संहिता प्रदान करते हैं। अधिनियम और शिक्षा विनियम , *अन्य बातों के अलावा,* स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि फार्मासिस्टों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम का संचालन कौन करेगा और पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की परीक्षा, अध्ययन की प्रकृति और अवधि और व्यावहारिक प्रशिक्षण का संचालन कौन करेगा। परीक्षा में प्रवेश से पहले किए गए कार्य, परीक्षा के विषय और उसमें प्राप्त किए जाने वाले मानक आदि।

(5) आगे यह दलील दी गई है कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) और शिक्षा विनियमों के विनियम 7 के तहत, फार्मेसी कॉलेज तरौरी को फार्मेसी में डिप्लोमा के दो साल के पाठ्यक्रम के संचालन के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार, अधिनियम और विनियम 12 की धारा I2(ii) के तहत, प्रतिवादी नंबर 1, यानी, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड हरियाणा (इसके बाद बोर्ड कहा जाएगा) को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालन के लिए परीक्षा प्राधिकारी के रूप में अनुमोदित किया गया है। की जांच

विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश मिला। आगे यह दलील दी गई है कि दो पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग-अलग प्राधिकरण बनाए गए हैं, एक फार्मासिस्टों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए और दूसरा उसके लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए। कॉलेज और आपकी परीक्षा संस्था अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च हैं और उनका अस्तित्व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कारण है।

(6) उपरोक्त फार्मेसी कॉलेज ने फार्मेसी के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए, जिसकी अंतिम तिथि 8 जुलाई, 1989 थी। प्रवेश के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, सत्र 1989-90 के लिए प्रवेश के लिए 120 छात्रों का चयन किया गया।उन्होंने अपनी फीस 9 से 16 जुलाई, 1989 के बीच जमा की। इस आशय की सूचना कॉलेज द्वारा बोर्ड को भेजी गई थी , - पत्र अनुबंध पीआई दिनांक 21 जुलाई, 1989 के माध्यम से। हालांकि, कॉलेज को आदेश अनुबंध पी 2 दिनांक 13 जुलाई 1989, को प्राप्त हुआ कि सत्र 1989-90 के लिए सभी निजी संस्थानों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों के सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश अंबाला में केंद्रीय रूप से किया जाएगा और उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी संस्थान असंबद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद, निदेशक, तकनीकी शिक्षा हरियाणा (कॉपी

अनुलग्नक पी 3) दिनांक 25 जुलाई, 1989 से एक और पत्र प्राप्त हुआ; बताया गया कि सत्र 1989-90 के लिए फार्मेसी में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कॉलेज द्वारा किए गए 120 छात्रों के प्रवेश को अमान्य घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कॉलेज ने अपने स्तर पर प्रवेश किए थे।

(7) यह अनुलग्नक पी2 और पी3 हैं जिन्हें इस याचिका के माध्यम से, *अन्य बातों के साथ,* निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है: -

(i) कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड केवल एक जांच निकाय है, और संलग्नक पी 2 और पी 3 पर लगाए गए आदेशों को पारित करने और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के तरीके के लिए कोई नीति निर्धारित करने में सक्षम नहीं है।

(ii) प्रवेश के तरीके के संबंध में एजेंडा अनुलग्नक पी 2 में उल्लिखित और फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश को पूरे हरियाणा में केंद्रीय रूप से करने के लिए , राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड हरियाणा के निदेशक मंडल या बोर्ड के किसी भी सक्षम निकाय के समक्ष नहीं रखा गया है जो इस तरह के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा ने अपना स्वयं का आदेश अनुलग्नक पी 2 पारित कर दिया है;

(iii) कि (उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थानों में समन्वय और मानकों के निर्धारण का विषय भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची संख्या 1 के अनुसार प्रविष्टि संख्या 66 में उल्लिखित है। न तो विधायी और न ही राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग तकनीकी संस्थानों के समन्वय के लिए किया जा सकता है। पूरे हरियाणा में केंद्रीय स्तर पर फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए चयन करने के लिए मानदंड निर्धारित करने की पूरी नीति 7वीं की सूची 1 की प्रविष्टि 66 के *दायरे से बाहर है।* भारत के संविधान की अनुसूची.

(iv) सत्र 1989-90 के लिए कॉलेज में प्रवेश पहले ही हो चुके हैं और परिशिष्ट पी2 में उल्लिखित विवादित नीति, यदि कोई हो, को इस सत्र के लिए प्रभावी नहीं बनाया जा सका।

(v) फार्मेसी अधिनियम, 1948 में दो अलग और स्वतंत्र प्राधिकरणों की परिकल्पना की गई है - (i) फार्मासिस्टों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए, और (ii) फार्मेसी में परीक्षा आयोजित करने के लिए, और बोर्ड के पास न तो पर्यवेक्षण की शक्ति है और न ही नियंत्रण की। पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले शरीर के क्षेत्र या गोले;

(vi) याचिकाकर्ता-कॉलेज को प्रवेश के तरीके का प्रबंधन और निर्णय लेने का अधिकार है, और उत्तरदाताओं को कॉलेज के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित नीति अनुबंध पी2 कॉलेज के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 19 I(l)(g) का उल्लंघन है।

(8) प्रतिवादी संख्या 3c1iiBoa की ओर से दायर किए गए रिटर्न में प्रारंभिक आपत्तियां ली गई हैं, उनमें से एक यह है कि याचिकाकर्ता को पहले से पता था कि प्रवेश केंद्रीय रूप से किया जाना था, और केंद्रीकृत प्रवेश में, प्रवेश किया जाना था। कैपिटेशन शुल्क को नजरअंदाज कर योग्यता के आधार पर। इसके बावजूद, बोर्ड और राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कॉलेज द्वारा अपने स्तर पर प्रवेश दिए गए, और इस प्रकार, 'याचिकाकर्ता ने दुर्भावना से काम किया। आगे कहा गया है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 52) लागू किया है, जिसके अनुसार फार्मेसी का पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मंजूरी आवश्यक है। उक्त परिषद, - इसके *द्वारा*

पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1989 (प्रतिलिपि अनुलग्नक आर-IV) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका पालन निजी तकनीकी

संस्थानों को करना होगा। चूंकि राज्य सरकार की केंद्रीकृत प्रवेश की नीति उपरोक्त अधिनियम के अनुरूप है, क्योंकि यह योग्यता के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करती है न कि दान/कैपिटेशन शुल्क लेकर, इसलिए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा अपने स्तर पर किया गया पूरा प्रवेश अनधिकृत है और इसलिए, रद्द किया जा सकता है, और छात्रों को तदनुसार केंद्रीय प्रवेश के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जा सकता है।

(9) योग्यता के संबंध में उल्लेख किया गया है कि फार्मेसी अधिनियम, 1948 के साथ-साथ राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के संबद्धता नियमों का भी पालन करना होगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 21 मार्च, 1989 के पत्र अनुलग्नक आर-VII के *माध्यम से* निर्देश दिया है कि फार्मेसी पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक संस्थानों को परीक्षा प्राधिकरण और संबद्धता पत्र का विवरण देना होगा। अब फार्मेसी पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम लागू है। रिटर्न के मुताबिक, न तो फार्मेसी एक्ट और न ही शिक्षा नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को कॉलेज के प्रवेश में हस्तक्षेप करने का कोई *अधिकार नहीं है।*

(10) रिटर्न में लिए गए रुख के अनुसार, प्रवेश संबंधी मामलों के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति और सहमति की आवश्यकता नहीं है। विवादित आदेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अनुरूप हैं। राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड संबद्ध प्राधिकारी और परीक्षा निकाय होने के नाते प्रवेश करने के लिए नीति निर्धारित करने में सक्षम है। यह कार्रवाई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अनुरूप है। राज्य सरकार और बोर्ड सरकारी और निजी संस्थानों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीति बनाने में सक्षम हैं। हरियाणा राज्य में चलाया जा रहा है। केंद्रीय प्रवेश का निर्णय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा के व्यवसाय के नियमों के नियम VIII में वर्णित उनकी विशेष शक्ति के तहत लिया गया है, जो "आपातकाल के मामलों में, बोर्ड की शक्तियों" का प्रावधान करता है। अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किया जाएगा और ऐसे मामलों को अनुसमर्थन के लिए बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाएगा।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला इस न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी नंबर (सेल ऑफ 198(1) में समाप्त हो गया है।

(अजय कुमार और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड आदि) ने 9 मार्च, 1987 को निर्णय लिया जिसमें यह माना गया कि प्रत्येक उम्मीदवार जो विनियम 10 में निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करता है, वह परीक्षा में बैठने का हकदार है। फार्मेसी में डिप्लोमा। बोर्ड द्वारा संचालित, - इसलिए, वे सभी छात्र जो फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमोदित संस्थानों के प्रमुखों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने नियमित रूप से और संतोषजनक ढंग से अध्ययन के दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम का पालन किया है और कम से कम 75 अंक प्राप्त किए हैं। सेंट लेक्चर क्या वह फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा। बोर्ड को ऐसी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने की तारीखों की अनुमति देने से इनकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। आगे यह माना गया है कि जो छात्र इन विनियमों के अनुसार पात्र हैं, उन्हें फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए रोका या अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, उक्त निर्णय के मद्देनजर, आदेश अनुलग्नक पी-2 और पी-3 रद्द किए जाने योग्य हैं। आगे प्रस्तुत किया गया है कि, फार्मेसी अधिनियम की धारा 46 के तहत, राज्य अध्याय 3, 4 और 5 के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से नियम बना सकता है, जो फार्मासिस्टों के आचरण और उनके कर्तव्यों से संबंधित हैं। चिकित्सकों, जनता और फार्मेसी के पेशे के संबंध में, जबकि अधिनियम की धारा 10 के तहत बनाए गए शिक्षा विनियम और धारा 12 के तहत प्रदान किए गए अध्ययन और परीक्षा के अनुमोदित पाठ्यक्रम अधिनियम के अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं, और, इसलिए राज्य सरकार के पास इन दोनों मामलों के संबंध में कोई भी नियम बनाने की शक्ति थी। विद्वान वकील के अनुसार, चूंकि जांच करने वाली संस्था यानी बोर्ड ही थी अधिनियम की धारा 12(2) के तहत अनुमोदित, यह इनकार नहीं कर सकता है कि 'यह छात्रों की परीक्षा आयोजित करेगा ii वे परीक्षा के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। कथित संबद्धता नियम क्रियोरी, क्योंकि राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड हरियाणा से संबद्धता के नियमों में कोई वैधानिक बल नहीं है। इसके अलावा, नियमों में ही, "संस्था" का अर्थ एक तकनीकी संस्थान है जो ' बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित इंजीनियरिंग या तकनीकी विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करता है, और

ऐसा होने के कारण उक्त' नियमों की फार्मेसी पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। संस्थान, 'एएनसीएफ', परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा संबद्धता का सवाल ही नहीं उठता। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 पहले के फ़ैनेसी अधिनियम को निरस्त नहीं करता है। दोनों को संचालन के अपने अलग-अलग क्षेत्र मिल गए हैं और एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करता है।' यहां तक कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम की धारा 10 के तहत, परिषद नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने के लिए मंजूरी दे सकती है, जिसका अर्थ है कि उक्त अधिनियम पहले वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता है।

संस्थाएँ। किसी भी मामले में, यदि याचिकाकर्ता -संस्थान द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है तो बोर्ड किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं होता है और संबद्धता नियमों की आड़ में बोर्ड छात्रों की परीक्षा आयोजित करने से इनकार नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है संस्थान। वास्तव में, विद्वान वकील के अनुसार, बोर्ड की ओर से रिटर्न में लिए गए रुख के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से बोर्ड के साथ किसी भी संबद्धता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह मामला भारत के संविधान की सूची संख्या 1 की प्रविष्टि संख्या 66 पर केंद्रीय विषय के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्य सरकार इस विषय पर कोई नियम नहीं बना सकती है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने पी. *राजेंद्रन* बनाम *मद्रास राज्य* (1) और *डीएवी कॉलेज, भटिंडा* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य* (2) का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश. अनुच्छेद 19(एल)(जी) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जिसे कार्यकारी आदेश द्वारा छीना नहीं जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने *सखारखेरदा एजुकेशन सोसाइटी* बनाम *महाराष्ट्र राज्य* (3), *शारदा एजुकेशन ट्रस्ट* बनाम *गुजरात राज्य* (4), *डी. भाव/उआन मोहन पटनायक का हवाला दिया।* बनाम *आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य* (5), *श्री द्वारका नाथ तिवारी* बनाम *राज्य* ओज *बिहार* (6)।

(12) दूसरी ओर, एडवोकेट-जनरल को पता चला कि फार्मेसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए शिक्षा विनियमों के तहत, पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था द्वारा किए जाने वाले प्रवेश के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 154 और 166 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 162 के तहत शक्तियों के प्रयोग में अंतर को भरने के लिए नियम बना सकती है। उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड उन लोगों की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं है जिन्हें फार्मेसी अधिनियम की धारा 12(1) के तहत अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है। किसी विशेष संस्थान के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करना बोर्ड का काम है, न कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को यह निर्देश देना कि बोर्ड किसी विशेष संस्थान के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य है। किसी के अभाव में उन्होंने वह भी प्रस्तुत कर दिया

(1) एआईआर 1968 एससी 1012।
(2) एआईआर 1971 एससी 1731।
(3) एआईआर 1988 बॉम्बे 91।
(4) 1976 गुजरात लॉ रिपोर्टर 298.
(5) एआईआर 1974 एससी 2092।
(6) एआईआर 1959 एससी 249 और. एआईआर 1958 एससी 296।

कमी को पूरा करने के लिए कानून, कार्यकारी शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने *राय साहिब राम जवाया कपूर* बनाम *पंजाब राज्य* (7), आंध्र प्रदेश राज्य बनाम *लवू नरेंद्र नाथ* (8), *बिशंभर दयाल चंद्र मोहन* बनाम *टीजेपी राज्य का उल्लेख किया।* (9) और ए. *मुरलीधर* बनाम *आंध्र प्रदेश राज्य* (10)।

(13) सीडब्ल्यूपी संख्या 6511/86 में फैसले के संबंध में, उन्होंने कहा कि उक्त मामला अलग-अलग है। किसी भी मामले में, उस फैसले के खिलाफ 1987 का एलपीए नंबर 338 और 339 इस न्यायालय में लंबित हैं, और, इसलिए, सीडब्ल्यूपी 6511/86 में फैसले की शुद्धता चुनौती के अधीन है। इसके अलावा, चूंकि वह क्षेत्र फार्मेसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए उक्त उद्देश्य के लिए नियम बनाना राज्य सरकार का काम था। अंत में, विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था और न ही याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड की ओर से कोई कानूनी दायित्व था, और कोई भी रिट नहीं दी जा सकती थी। प्रार्थना के अनुसार जारी किया गया।

(14) पक्षों के वकील को सुनने के बाद, मेरी सुविचारित राय है कि वर्तमान मामला (*अजय कुमार और अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, चंडीगढ़ और अन्य* (11)) में इस न्यायालय के फैसले से पूरी तरह से कवर होता है। इसमें भारतीय फार्मेसी अधिनियम और शिक्षा विनियमों के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उस याचिका में, जनता कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बुटाना, जिला सोनीपत के छात्रों ने बोर्ड को दिसंबर 1986 में उन्हें बैठने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। परीक्षा। वहां बोर्ड द्वारा यह रुख अपनाया गया कि छात्र द्वितीय वर्ष में अपने प्रवेश के नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते, जो उन्हें सोनीपत के जनता कॉलेज के प्रिंसिपल की मिलीभगत से मिला था। उक्त विवाद को निरस्त कर दिया गया और अंततः, यह माना गया कि "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अकादमिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को मंजूरी देने का अधिकार परिषद में निहित है। यह परिषद ही है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम को नियंत्रित करती है जिसमें शैक्षणिक सत्र की शुरुआत, सत्र की अवधि और अन्य संबद्ध और संबंधित मामले। परीक्षा आयोजित करने वाली अथॉरिटी के पास नहीं है

(7) एआईआर 1955 एससी 549।
(8) एआईआर 1971 एससी 2560।
(9) (1982) 1 एससीसी 39।
(10) एआईआर 1959 एपी 437।
(11) 1986 का सीडब्ल्यूपी 6511 9 मार्च, 1987 को तय किया गया।

इन मामलों में कहें. परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य विनियम 8 से 10 से प्रवाहित और विनियमित होते हैं।" इसमें आगे कहा गया कि नियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियमित शैक्षणिक अध्ययन के पाठ्यक्रमों को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा संचालित किया जाना है जिसे परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित किया गया है। परिषद के पास अपने मामले पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति है। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार जो विनियमन 10 में निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करता है, वह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आयोजित डिप्लोमा इन फार्मेसी (भाग आईआईए) के लिए परीक्षा में उपस्थित होने का हकदार है। इसलिए सभी छात्र जो संस्थान के प्रमुख से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं फार्मेसी का संचालन करने वाले इस प्रमाण में कि उन्होंने दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम का नियमित रूप से पालन किया है और कम से कम 75 प्रतिशत कक्षाओं में भाग लिया है और डिप्लोमा इन फार्मेसी (भाग-1) के लिए परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है, वे इसमें उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग IIA) के लिए परीक्षा। प्रतिवादी नंबर 1 के पास ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई विवेक नहीं है।"

(15) समानता से इसी प्रकार, मौजूदा रिट् पेटिशन में उन छात्रों को याचिकाकर्ता-संस्था द्वारा प्रवेश दिया गया है और यदि वे 1981 के शिक्षा नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो वे बोर्ड द्वारा जांच के हकदार हैं। चूंकि बोर्ड शिक्षा विनियमों के

साथ पढ़े जाने वाले भारतीय फार्मेसी अधिनियम के तहत परीक्षा निकाय है, इसलिए यह याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिसे फार्मेसी काउंसिल द्वारा भारतीय फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत अनुमोदित किया गया है। भारत। विनियम 7 के तहत विनियम 5 के तहत दिए गए नियमित शैक्षणिक अध्ययन का पाठ्यक्रम एक राज्य में एक प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा धारा 12 के उपधारा (1) के तहत केवल तभी मंजूरी दी जाएगी जब वह इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था प्रदान करता हो। इन विनियमों के परिशिष्ट-बी में निर्दिष्ट अनुसार भवन, आवास, उपकरण और शिक्षण स्टाफ के संबंध में शिक्षण। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह मंजूरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा धारा 12 की उपधारा (1) के तहत दी गई है। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि धारा 12(1) के तहत, अनुमोदन केवल तभी दिया जाएगा जब केंद्रीय परिषद ऐसी जांच के बाद संतुष्ट हो जाए क्योंकि वह उचित समझती है कि अध्ययन का पाठ्यक्रम विनियमों के अनुरूप है। उक्त उद्देश्य के लिए समय-समय पर केंद्रीय परिषद ने बोर्ड से ही यह पूछताछ की और बोर्ड से की गई जांच के बाद ही इसके तहत आवश्यक मंजूरी दी गई।

धारा 12 की उपधारा (1) प्रदान की गई। यदि बोर्ड को लगता है कि याचिकाकर्ता-संस्थान अपने संबद्धता नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है या प्रावधानों की पुष्टि नहीं करता है। शिक्षा विनियमों के अनुसार, बोर्ड को अगले वर्ष के लिए अपनी मंजूरी वापस लेने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को मामले की रिपोर्ट करने की छूट थी। जब तक याचिकाकर्ता को धारा 12 की उपधारा (1) के तहत मंजूरी दी गई है, उसके छात्र धारा 12 की उपधारा (2) के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित होने के कारण बोर्ड द्वारा जांच के हकदार होंगे। संबद्धता नियमों की आड़ में बोर्ड को याचिकाकर्ता-संस्थान द्वारा छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वस्तुतः उक्त संबद्धता नियम याचिकाकर्ता-आरंभ से संबंधित नहीं हैं जो फार्मासिस्टों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करता है। संबद्धता नियमों के तहत, संस्थान को एक "तकनीकी संस्थान जो डिप्लोमा/सैंटीफ़ियोएट पाठ्यक्रम संचालित करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की कोई भी शाखा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि इसमें याचिकाकर्ता-संस्थान शामिल नहीं है जो फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संबद्धता. बोर्ड द्वारा तकनीकी संस्थानों के संबंध में नियम केवल इसलिए बनाए गए क्योंकि बोर्ड न केवल फार्मासिस्टों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, जैसा कि धारा 12 की उपधारा (2) के तहत अनुमोदित है, बल्कि अन्यथा भी।

(16) जहां तक 1987 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 52 यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 का संबंध है, जो 11 मार्च, 1988 को लागू हुआ, इसकी याचिकाकर्ता -संस्था पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। उपधारा के अंतर्गत. इसकी धारा 10 के 1 खंड (के) में परिषद के कर्तव्य बताए गए हैं। उनमें से एक संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नए तकनीकी संस्थान शुरू करने और कार्यक्रमों के नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी देना है। इस प्रकार, ऐसा अधिनियम नए तकनीकी संस्थानों पर लागू होता है, न कि उन संस्थानों पर जिन्हें भारतीय फार्मेसी अधिनियम के तहत पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा, पहले के अधिनियम को इस अधिनियम संख्या 52, 1987 द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। दोनों अलग-अलग कार्य कर रहे हैं और इसलिए, बोर्ड याचिकाकर्ता-संस्था के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए 1987 के उक्त अधिनियम 52 से कोई सहायता नहीं ले सका। माना कि उत्तरदाताओं द्वारा इसे किसी भी प्रकार की कोई अनुदान सहायता नहीं दी जा रही है।

(17) इसके अलावा, फार्मेसी अधिनियम की धारा 46 में प्रावधान है कि राज्य सरकार अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। III, IV और V. अधिनियम की धारा 12 के संबंध में, जो इससे संबंधित है

अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रम की मंजूरी उसके अध्याय- II के अंतर्गत आती है। ऐसा होने पर, राज्य सरकार अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रमों के संबंध में कोई नियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं थी, जैसा कि अधिनियम के अध्याय II की धारा 12 के तहत विचार किया गया है।

(18) प्राधिकारियों ने तत्कालीन वकील के आश्वासन पर भरोसा किया कि जब कोई नियम नहीं हैं, तो राज्य सरकार अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत नियमों का पालन कर सकती है, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं की ओर से यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि संस्थान में प्रवेश के संबंध में जिसे उपधारा 1 के तहत मंजूरी दी गई है। फार्मेसी अधिनियम की धारा 12, वे अपने स्वयं के प्रॉस्पेक्टस के अनुसार प्रवेश करने के हकदार नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि संस्थान को राज्य सहायता आदि दी जाती, तो वह इसके प्रवेश को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी सहायता के अभाव में, संस्थान में प्रवेश को प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था।

. (19) इन परिस्थितियों में परिशिष्ट पी-2 में निर्देश है कि सभी नान-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम फार्मेसी सहित जो कि याचिकाकर्ता-संस्थान यानी महर्षि कॉलेज ऑफ फार्मेसी ताराओरी द्वारा संचालित किए जाते हैं वह सरकारी पॉली टेक्निक फॉर वुमेन, अंबाला शहर में आयोजित किए जाएंगे, और इसी तरह के अन्य निर्देश हैं कि "कोई भी संस्थान अपना स्वयं का प्रॉस्पेक्टस जारी करने और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं है; अपने स्तर पर गैर-इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रम। किसी भी संस्थान/पॉलिटेक्निक में सीधे प्रवेश चाहने वाला कोई भी छात्र ऐसा अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर करेगा और ऐसे छात्र की परीक्षाएं राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा द्वारा आयोजित नहीं की जाएंगी। उपरोक्त प्रवेश प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाला कोई भी संस्थान असंबद्धता के लिए उत्तरदायी होगा " इसकी गारंटी नहीं है। इसी प्रकार, अनुलग्नक पी-3 में यह निर्देश दिया गया है कि "यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी संस्थान द्वारा इस कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने स्तर पर प्रवेश दिया जाता है, तो ऐसे प्रवेश पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा और इस प्रकार प्रवेशित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।" पंजीकृत होना और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देना", याचिकाकर्ता संस्थान के संबंध में भी मान्य नहीं है। नतीजतन, 1989 के सीडब्ल्यूपी 12033 के साथ रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है। अनुलग्नक पी-2 और टीपी-3 में दिए गए ऐसे निर्देश याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लागू नहीं किए जाएंगे।

(20.) रिट याचिका संख्या 11768, 11525, 11566 और 11760 और 1989 उन छात्रों द्वारा दायर की गई है जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है।

निजी संस्थानों द्वारा जिन्हें भारतीय फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के तहत विधिवत अनुमोदित किया गया है। बोर्ड के अनुसार, चूंकि छात्रों ने अपनी पहली प्राथमिकता एक विशेष संस्थान को दी है, इसलिए, उन्हें उक्त संस्थानों द्वारा प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, चूंकि उक्त संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने के लिए बोर्ड द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्हें कोई राज्य सहायता नहीं मिल रही थी, इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ता राज्य के स्वामित्व वाले संस्थानों में अपने प्रवेश के उद्देश्य के लिए योग्यता के आधार पर विचार करने के हकदार होंगे। संस्थाएँ। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि मेरिट में आने वाले याचिकाकर्ताओं को केवल इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने उन संस्थानों को अपनी प्राथमिकता दी है जो उन्हें अब शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर वे मेरिट में आते हैं तो बोर्ड उस पर विचार करेगा और उसी के अनुरूप उन्हें अन्य संस्थानों में प्रवेश देगा। नतीजतन, ये सभी याचिकाएं लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के ऊपर बताई गई सीमा तक सफल होती हैं।

(21) 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9981 में, याचिकाकर्ता संस्थान के छात्रों ने वर्तमान रिट याचिका में पक्षकार बनने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत एक आवेदन किया। ऐसे छात्र न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्षकार हैं। इसलिए, यह सिविल विविध आवेदन खारिज किया जाता है।

आरएनआर

न्यायमूर्ति ए.एल. बहरी के समक्ष

चमन लाल, - *अपीलकर्ता,*

बनाम

पंजाब राज्य व अन्य,-प्रतिवादीगण

1986 *की नियमित द्वितीय अपील संख्या* 410

12 मार्च, 1990.

पंजाब सिविल सेवा (समयपूर्व सेवानिवृत्ति) नियम , 1975- *नियम।* 2, 3, 5 एवं 6- *जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति- सक्षम प्राधिकारी- सेवा रिकार्ड पर विचार-* की आवश्यकता *ऐसा विचार.*

माना गया कि सेवानिवृत्ति के समय, अपीलकर्ता सेशन डिवीजन में रिकॉर्ड-कीपर के रूप में काम कर रहा था। यह जिला और सत्र न्यायाधीश है जिसके पास जिला न्यायालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। हो सकता है कि शुरुआत में अपीलकर्ता ने ऐसा किया हो